(b) Neyveli Lignite Corporation Ltd. were instructed to take all possible steps to restore the production of lignite from the Second Mine and to ensure generation of power from the Second TPS as early as possible. Besides, the NLC Ltd. were instructed to draw up short term action plans for strengthening the surface drainage arrangements and were advised to interact with the State Government Authorities for long term measures.

Prompt actions were taken by the NLC management to dewater the Mine II. The dewatering of flood water was satisfactorily achieved by the first week of January, 1992. Parallel actions were taken by the management for recommissioning the overburden production system after making necessary retrievable operations. The overburden removal restarted from 19th November, 1991 and stabilised gradually. The lignite production was recommenced on 2nd January, 1992 after strenuous cleaning operation of flood deposit silt. All the submerged mining and electrical equipments were successfully restored and recommissioned after carrying out necessary maintenance works.

Losses suffered by the coal mines under BCCL

1216. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some coal mines under BCCL have been running under losses;

(b) if so, the steps taken by Government to overcome the losses; and

(c) whether Government propose to take over BCCL?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) Coal India Limited (CIL) have informed that an action plan is being drawn up to improve the viability of Bharat Coking Coal Limited (BCCL). It includes steps for increase in production, improvement in productivity and optimum deployment of personnel so as to improve the economics of the losing mines. However, even after these actions, some mines in Bharat Coking Coal Limited may continue to lose because of inherent geo-mining problems.

(c) Bharat Coking Coal Limited is a subsidiary of Coal India Limited, which in turn is owned by Government. As such the question of Government taking over Bharat Coking Coal Limited does not arise.

विभिन्न किस्मों के कोयले के मूल्यों के निर्धारण का आधार

1217. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कोयले के मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि के पश्चात् किन आधारों पर विभिन्न किस्मों के कोयलों के प्रतिटन मूल्यों का निर्धारण किया गया है;

(ख) इस वृद्धि के परिणामस्वरूप कोल इंडिया लिमिटेड की लाभकारिता पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन चल रही उन कोयला खानों का ब्यौरा क्या है जो घाटे में चल रही हैं तथा जो लाभ कमा रही हैं; और

(घ) इन हानियों पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० बी० नयमेगौड़ा) : (क) दिनांक 28-12-91 से कोयले की विभिन्न ग्रेडों की कीमतों में प्रभावी वृद्धि, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा सिफारिश किए गए वृद्धि मामले पर आधारित हैं ।

(ख) कोल इंडिया लि० को औसतन 73 रुपये प्रति टन की वृद्धि किए जाने की अनुमति दी गई है और इस वृद्धि के परिणामस्वरूप कोल इंडिया लि० के मामले में इस संबंध में 28-12-1991 से 31-3-1992 की अवधि के दौरान 480 करोड़ रुपये की अधिक राशि प्राप्त होने का अनुमान है ।

(ग) कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्ष 1990-91 में कोल इंडिया लि० की 6 कोयला उत्पादन करने वाली सहायक कंपनियों द्वारा कार्यचालित 397 कोयला खानों में से 300 खानें घाटे में चल रही हैं, जबकि 97 खानें लाभ कमा रही थी । इस आंकड़े के प्रयोजन के लिए कोयला उत्पादन करने वाली यूनिटें "खानों" के रूप में ऐसी खानें हैं, जो कि लागत संबंधी सूचना दिए जाने के लिए लागत केन्द्र के रूप में समझी जाती हैं । अतः इस स्थान पर "खान" के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़े अन्य प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुरूप न समझे जाएं ।

(घ) घाटे को कम किए जाने के संबंध में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

(1) श्रमशक्ति आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू कामगारों की पुनः तैनाती और प्राकृतिक रूप में फिजूलखर्ची के कारण रिक्त पदों के एवज में नए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाया जाना शामिल है ।

(2) श्रमशक्ति में वृद्धि पर स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के जरिए नियंत्रण ।

(3) "आल मैन-आल-जाब" की संकल्पना को प्रायोगिक आधार पर प्रयोग में लाया जा रहा है ।

(4) पर्याप्त रूप में वर्कशाप-स्पोर्ट, स्पेयर पुर्जों की व्यवस्था में सुधार और उपकरणों की समय पर विस्थापन करके उपकरणों की उपयोगिता तथा उपलब्धता में सुधार ।

(5) भूमिगत खानों पर विशेष जोर देकर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि ।

(6) कार्यचालन की दक्षता में सुधार लाए जाने के लिए कई सुधार पद्धतियां तथा प्रबंधनीय उपाय अंगीकृत किए गए हैं ।

ईंट भट्टा उद्योग को कोयले की कम सप्लाई

1218. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 फरवरी, 1992 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कोयले की कमी के कारण ईंट भट्टा उद्योग बन्द होने के कगार पर पहुंच गया है;

(ख) गत छः महीनों के दौरान इस उद्योग को कितने रेक कोयला प्रतिमाह उपलब्ध कराया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० बी० नयमेगौड़ा) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले 6 महीनों की अवधि के दौरान रेल द्वारा कोल इंडिया लि०